

2/17

श्रीगंगानगर
जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

A2
2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

करण संख्या :-02/17

वर्ष:- 2017

ठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

वर्तमान पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तहसील श्री करणपुर---अपीलांत
बनाम

कालू राम पुत्र बहादर राम जाति जाट निवासी 20 एफ एफ मोटासर खूनी त0 करणपुर
दया राम पुत्र हरी राम जाति जाट निवासी 20 एफ एफ मोटासर खूनी त0 श्रीकरणपुर
स्टेट आफ राजस्थान --- रैस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 418 दिनांक 25.01.17 जिसके द्वारा
अपीलांत की भूमि विधि विरुद्ध रैस्पोंडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किये
जाने का आदेश दिया गया निरस्त करने बाबत।

॥ निर्णय ॥

दिनांक:- 11/4/17

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं अपीलांत द्वारा अपील हाजा पेश अदालत की गई कि रैस्पोंडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट यह कथित करते हुए पेश किया गया कि रैस्पोंडेंट वाके चक 20 एफ एफ तह0 श्रीकरणपुर के जमाबंदी संवत् 2066-2069 के संयुक्त खाता संख्या 32 के मु. नं. 31, 32,33,35,37,52 व मु. नं. 87/25 की 12.027 हैक्. भूमि में से 116-23/24 हिस्सा का अन्य खातेदार के साथ सहखातेदार है और उक्त संयुक्त खाता में मु. नं. 31 के किला नं. 4 ता. 8 व 13 पर काबिज है और रैस्पोंडेंट इसी चक 20 एफ एफ के मु. नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, 9,10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक सालम तथा किला नं. 21, 22, प्रत्येक में 18-18 बिस्वा रकबा नहरी तथा मु. नं. 87/7 का 0.063 हैक्टर मु. खाता कुल 2.947 हैक्टर भूमि का खातेदार है और मु. नं. 38 के किला नं. 1, 10, 11, 20,21 व मु. नं. 30 के किला नं. 1 ता. 5 व किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मंजूर शुदा चालू और रैस्पोंडेंट संख्या 1 मु.नं. 31 के किला नं. 1, 2,3 में से चलकर अपनी भूमि किला नं. 4 में प्रवेश करता है और अप्रार्थी संख्या 2 रैस्पोंडेंट ने मु0 नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, में से रास्ता बंद कर दिया गया है और रैस्पोंडेंट को कठिनाई होती है व मुख्या नंबर 31 के किला नं. 1, 2, 3 में से 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जावें। रैस्पोंडेंट संख्या 2 हाजिर आया और जवाबदेही कि रैस्पोंडेंट संख्या 1 खाता संख्या 32 की संयुक्त भूमि में एक खातेदार है और रैस्पोंडेंट मु. नं. 31 के किला नं. 4, 5, 6, 7, 8 व 13 पर काबिज नहीं है और इस संयुक्त खाता की अन्य भूमि पर काबिज है और इस संयुक्त खाता की भूमि के लिए मु. नं. 37 के किला नं. 21 से 25 के चिपता हुआ मु. नं. 51 के किला नं. 1 ता0 5 में रास्ता है और अप्रार्थी मु. नं. 51 में चल रहे मु. नं. 37 के किला नं. 25, 16, 15, 6 में प्रवेश कर रैस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपने चाचा के किला नं. 5 में प्रवेश कर मु0 नं. 31 में प्रवेश करता है क्योंकि रैस्पोंडेंट संख्या 1 के चाचा को भी किला नं. 5 में आने के लिए रैस्पोंडेंट के किला नं. 6, 15, 16, 25, में से ही निकलना पड़ता है उक्त संयुक्त खाता की भूमि के लिए मु. नं. 31 में से कभी कोई रास्ता न तो था व न है। मु. नं. 30 के किला नं. 1 ता. 5 व किला नं. 10, 11, 20, 21 में रास्ता रैस्पोंडेंट संख्या 2 को भूमि विभाजन में सन 2011 में ही स्वीकृत किया गया है। सन 2011 से पूर्व मु. नं. 30 में कोई रास्ता नहीं था। इसलिए रैस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा मु. नं. 30 व 31 के किला नं. 1, 2, 3, में रास्ता होने की बात झूठी थी। मु. नं. 31 के किला नं. 1 में अप्रार्थी रैस्पोंडेंट संख्या 2 की रिहायशी ढाणी बनी हुई है और प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के बाद सुनवाई अपीलांत की भूमि मु. नं. 31 के किला नं. 1, ता. 3 में 2-2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया है। और इस संबंध में तहसीलदार हल्का को पत्र लिखा। तहसीलदार हल्का ने विधि विरुद्ध कार्य करते हुए राजस्व रिकार्ड में अपीलांत की भूमि होने के बावजूद अपीलांत को नोटिस जारी न कर रैस्पोंडेंट संख्या 2 को नोटिस जारी किया और इतकाल संख्या 418 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांत बाद प्रस्त भूमि का खातेदार है। अपीलांत को बिना सुनवाई का अवसर दिये इतकाल स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को माननीय न्यायालय की अनुमति से अपील के माध्यम से चुनौति देने का अधिकारी है। यह कि राजस्व रिकार्ड में मु. नं. 31 के किला नं. 1 ता. की भूमि अपीलांत के नाम खातेदारी दर्ज है। अपीलांत की ढाणी किला नं. 1 में बनी हुई है। उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर में प्रकरण संख्या 25/13 के माध्यम से रैस्पोंडेंट संख्या 2 की भूमि में रास्ता स्वीकार करने का आदेश दिया था। अधीनस्थ न्यायालय व हल्का

कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

2/17

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकंता)
श्रीगंगानगरA2
3

पटवारी व गिरदावर को बाद ग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम होने की पूर्ण जानकारी थी और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग कर अपीलांट की भूमि का इतकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इतकाल से अपीलांट के नाम भूमि का इतकाल दर्ज किया परंतु नोटिस रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 के नाम जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश पालना के लिए अवश्य आया था, परंतु अपीलांट की भूमि बाबत नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर से राजस्व रिकार्ड की सही स्थिति स्पष्ट कर ही कोई आदेश प्राप्त कर इतकाल बाबत आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपीलांट की भूमि बिना किसी आदेश से बिना आधार विधि विरुद्ध रास्ता के नाम दर्ज करने में सख्त गलती की है। हल्का पटवारी ने अपीलाधीन इतकाल दर्ज करते समय नोट अवश्य अंकित किया है कि जरिये इतकाल संख्या 379 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा उक्त भूमि दयाराम रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अपने पुत्र के पक्ष में दान कर दी है। इस नोट के दर्ज होने से भू-अभि. निरीक्षक हल्का पटवारी व तहसीलदार ने इतकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय व हल्का पटवारी द्वारा किये गये विधि विरुद्ध कार्य को अपना ज़िम्मेदारी कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि बैंक के रहन थी और बैंक को बिना सुने बैंक के नाम की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर ने मु. नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, में 2-2 बिस्वा रास्ता की भूमि के बदले में रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 की भूमि के बदले में मु. नं. 31 में ही भूमि अप्रार्थी को देने का आदेश दिया था। हल्का पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय ने मु. न. 31 की भूमि न देकर संयुक्त खाते में भूमि दी है जो आदेश विपरीत व विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में इतकाल स्वीकृत करते समय भू-राजस्व अधिनियम के नियम 121 से 127 की पालना न कर आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। इतकाल तस्दीक करने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी है। अधीनस्थ न्यायालय को इतकाल स्वीकृत करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि की हल्का पटवारी से जमाबंदी 24.01.2017 को प्राप्त की थी और हल्का पटवारी ने इतकाल में उक्त दिनांक को दर्ज करना अंकित किया है। उक्त दिनांक को ही रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 19.01.2017 को स्थगित करने का अनुतोष मांगा था और इसकी सूचना पटवारी हल्का को दे दी थी और उपखंड अधिकारी ने दिनांक 27.01.2017 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था व पीछे की तारीख में इतकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलांट को दी गयी जमाबंदी में ऐसा कोई अंकन नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का जरिये रजि० दानपत्र दिनांक 03.07.2014 से खातेदार मालिक है। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज है। भूमि के इतकाल संख्या 418 बाबत कोई जानकारी अपीलांट को नहीं थी। जानकारी के आधार पर अपील को प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंड की ओर से श्री जगमोहन आहूजा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व पैरवी की गई।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलान्त के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराया गया व कथन किया गया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि उभय पक्षों को सुना जाकर ही न्याय निर्णयन किया जाये। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा नजीर आर आर डी 1995 पेज 772, आर आर डी 2002 पेज 338 पेश की।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोंडेन्टस द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील भाई नहीं करती क्योंकि अपीलाधीन आदेश न्यायालय द्वारा सविवेक नहीं दिया गया व न ही रिकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर पारित किया गया है वरन् अपीलाधीन आदेश उपखण्डाधिकारी के आदेशों की पालना मात्र है। अतः अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

समायत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। नजीर आर आर डी 2002 पृष्ठ 338 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अविवादित नामान्तरण को तस्दीक करने की शक्तियां संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदत्त हैं यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता तो शक्तियां तहसीलदार में हस्तान्तरित हो जाती हैं, नजीर आर आर डी 1995 पेज 772 में मुरतहिन को सुना जाकर निर्णय किया जाना चाहिये लेकिन मेरे विनम्र मत में उक्त नजीरों इस प्रकरण पर इसलिये चर्चा नहीं होती क्योंकि प्रकरण हाजा में तहसीलदार द्वारा स्व-विवेक से इतकाल नहीं किया गया है वरन् उपखण्डाधिकारी के आदेश की पालना की गई है। अवलोकन से पाया गया कि

क्टर (सतकंता)

पर

2/17

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकंता)
श्रीगंगानगर

A2
4

अपील अपीलांत द्वारा इन्तकाल संख्या 25.01.2017 के विरुद्ध पेश की गई है तथा उपखण्डाधिकारी किरणपुर द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी चक नम्बर 20 एफ एफ के किला नम्बर 1-2-3 तादादी 2-2 विस्वा रास्ता स्वीकृति के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह आदेश उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 19.01.2017 की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा किया गया है। जो अपील गय नहीं है क्योंकि इस इन्तकाल में अपीलांत को इसी इन्तकाल के द्वारा किला नम्बर 1-2-3 में से 075 हैक्टर में आदेश की पालना में पर्वत सिंह के खाते में दर्ज की गई है। वस्तुतः न्यायालय के मूल आदेश के विरुद्ध ही अपील संरिथत की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश मूल आदेश न होकर अपने से उच्चतर न्यायालय के आदेशों की पालना मात्र है। इसमें अपीलांत के खाते में किला नम्बर 1-2-3 में रास्ता स्वीकृत किया गया है उसके बदले भूमि की इसी इन्तकाल के जरिये दी गई है। उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 19.01.17 के विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष विचाराधीन है।

- आदेश -

समग्र अवलोकन के पश्चात उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के प्रकाश में अपील लाई नहीं होने के कारण रिज की जाती है इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश 13.02.2017 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ संबंधित रिकार्ड लौटाया जावे। पालना सुनिश्चित होकर पत्रावली बाद तीव तकमील हरब जाब्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतकंता)
श्रीगंगानगर